Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

दिसंबर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ के चार और अस्पतालों को मिला एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन	3
निजी क्षेत्र में स्थापित देश का पहला मछली अनुसंधान केंद्र	3
छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ 'लैंड एडवेंचर पुरस्कार' से सम्मानित	4
विधानसभा अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री ने बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना	4
भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में दी 7 खेलो इंडिया सेंटर की मंज़ूरी	5
छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोज़गारी	5
स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी ज़िला सुकमा देश में प्रथम	6
मुख्यमंत्री ने किया बिलासपुर एवं अंबिकापुर में रीजनल सी-मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन	7
बुजुर्गों, दिव्यांगजन और तृतीय लिंग समुदाय के लिये हेल्पलाईन सुविधा शुरू	7
राजस्व मंत्री ने किया राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन	8
मुख्यमंत्री ने देवभोग में लघु वनोपज उत्पाद पार्क का भूमिपूजन किया	8
सरायपाली का शिशुपाल पहाड़ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा	9
मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 57वीं किस्त का ऑनलाईन अंतरण किया	9
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को किया जाएगा सम्मानित	10
जी-20 समूह की बैठक अगले साल छत्तीसगढ़ में होगी	11
शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता प्रारंभ	11
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को किया सम्मानित	12
राज्य भर में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस	13
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यों का संचालन अब समग्र शिक्षा से	13
एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर	14
मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवर ब्रिज का किया लोकार्पण	14
'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'	15
मुख्यमंत्री ने 'न्याय के चार साल'एवं 'न्याय के रास्ते-सबके वास्ते' पुस्तकों का किया विमोचन	15
छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे बाघ	15
राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी विशेष पुस्तक 'बैक फ्राम दी ब्रिंक' का विमोचन	16
छत्तीसगढ़ के 'मोर मयारू गुरूजी' कार्यक्रम को मिला राष्ट्रीय सिल्वर स्कॉच अवार्ड	17
पुरातत्त्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा संस्कृति एवं राजभाषा का पृथक्-पृथक् संचालनालय	18
अब होटलों के मेन्यू में शामिल होंगे मिलेट्स के बने व्यंजन	18
मुख्यमंत्री ने सोनाखान में ओपन एयर म्यूजियम और बलौदाबाज़ार-भाटापारा टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया	19
एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ ने 58 पदक लेकर पाँचवां स्थान प्राप्त किय	20
करमा एथनिक रिसॉर्ट मैनपाट व जोहर मोटल का हुआ लोकार्पण	20
राज्यपाल ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहसी वीर बालक और बालिकाओं को किया सम्मानित	21
छत्तीसगढ़ वन अधिकार क्रियान्वयन में देश में अग्रणी	22
अंतर्राष्ट्रीय वन मेला: छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को अंतर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार	23
प्रदेश के सभी ज़िलों में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण	23
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय	24
'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति	25

नोट :

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के चार और अस्पतालों को मिला एनक्यूएएस सर्टिफिकेशन

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के चार और सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र (National Quality Assurance Standard Certificate) प्रदान किया है। इनमें धमतरी ज़िले के दो तथा दुर्ग व रायगढ़ के एक-एक अस्पताल शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धमतरी ज़िले के गेदरा और गाड़ाडीह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC) उप स्वास्थ्य केंद्र, दुर्ग के अहेरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र तथा रायगढ़ के रामभाटा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एनक्यूएएस प्रमाण-पत्र जारी किया है।
- भारत सरकार की टीम द्वारा अस्पताल के विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन में गाड़ाडीह उप स्वास्थ्य केंद्र को 94 प्रतिशत, गेदरा उप स्वास्थ्य केंद्र और रामभाटा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 90-90 प्रतिशत तथा अहेरी उप स्वास्थ्य केंद्र को 87 प्रतिशत अंक मिले हैं।
- अब तक प्रदेश के कुल 61 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा चुका है। इनमें दस ज़िला अस्पताल, सात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पाँच उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।
- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन के लिये अस्पतालों का 12 मानकों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिये अस्पताल द्वारा सेवा प्रदायगी, मरीज संतुष्टि, क्लिनिकल सर्विसेस, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेस, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आउटपुट जैसे मानकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

निजी क्षेत्र में स्थापित देश का पहला मछली अनुसंधान केंद्र

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बलौदाबाज़ार-भाटापारा ज़िले के ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र स्थापना की गई है। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह केंद्र छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का पहला केंद्र है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉ. सी. सुवर्णा ने अपनी दो-दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान रामपुर में संचालित मछली पालन की एक्वा जेनेटिक केंद्र का अवलोकन किया। साथ ही डॉ. सुवर्णा ने बलौदाबाज़ार-भाटापारा ज़िले के सिमगा विकासखंड के ग्राम बाईकोनी में स्थित प्रतिदिन 100 टन उत्पादन की क्षमता वाले वृहद निजी मत्स्य आहार केंद्र का शुभारंभ भी किया।
- एक्वा जेनेटिक के इस केंद्र की स्थापना एम हेचरी रायपुर एवम् मनीत ग्रुप थाईलैंड के संयुक्त उपक्रम द्वारा की गई है। इस अनुसंधान केंद्र में थाईलैंड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही प्रशिक्षण भी देंगे।
- लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैले इस अनुसंधान केंद्र में मछली के जेनेटिक्स पर अनुसंधान के साथ-साथ तिलापिया मछली बीज का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ मत्स्य कृषकों को मछली पालन के अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- ग्राम रामपुर में स्थापित अनुसंधान केंद्र से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों को उन्नत किस्म के मछली के बीज की आपूर्ति हो सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेगा। इसके अलावा वृहद मत्स्य आहार केंद्र के प्रारंभ होने से प्रदेश के किसानों को स्थानीय स्तर पर कम दर पर मत्स्य आहार प्राप्त हो सकेगा।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। अब यहाँ मछली अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की इकाईयाँ भी आगे आ रही हैं।

नोट :

- डॉ. सुवर्णा ने सिमगा विकासखंड के ग्राम खेरवारी में बंद हो चुके खदानों में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा केज कल्चर विधि से किये जा रहे मछली पालन का भी अवलोकन किया। समूह द्वारा यहाँ मछली पालन के लिये 12 केज तैयार किये गए हैं। इसके लिये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत और डी.एम.एफ से 40 प्रतिशत अनुदान दिया गया है।
- अपने प्रवास के दौरान डॉ. सुवर्णा ने रायपुर ज़िले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम पीकरीडीह स्थित वृहद बायोफ्लोक यूनिट का भी अवलोकन किया। इस यूनिट की स्थापना के लिये कृषक अंजू मिश्रा को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि अनुदान में मिला है। इस इकाई में तिलापिया और सिंगी मछली का पालन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ 'लैंड एडवेंचर पुरस्कार' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 'लैंड एडवेंचर पुरस्कार'से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय लैंड एडवेंचर पुरस्कार के लिये बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को चुना था। नैना सिंह धाकड़ यह राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई हैं।
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार चार श्रेणियों- लैंड एडवेंचर (भूमि साहसिक), वॉटर एडवेंचर (जल साहसिक), एयर एडवेंचर (वायु साहसिक) और लाइफ टाइम अचीवमेंट (जीवनभर की उपलब्धि) में दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रत्येक श्रेणी में 15 लाख रुपए और स्मृति चिन्ह के साथ प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।
- तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रतिवर्ष साहसिक कार्य के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धि की प्रशंसा के लिये दिये जाते हैं। यह पुरस्कार लोगों को धीरज, जोखिम लेने, सहकारी टीम वर्क और त्वरित सजगता की भावना विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- गौरतलब है कि नैना सिंह धाकड़ ने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊँची चोटी माउंट ल्होत्से में 10 दिनों के भीतर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था। नैना धाकड़ यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही है।

विधानसभा अध्यक्ष एवं कृषि मंत्री ने बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

चर्चा में क्यों ?

1 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कृषि मंत्री के निवास से बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- यह रथ 15 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भ्रमण करेगा और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करेगा।
- उल्लेखनीय है कि रबी मौसम वर्ष 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 1 से 7 दिसंबर के मध्य चौथा फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा से होने वाले लाभ, साथ ही फसल बीमा लेने की प्रक्रिया और लाभार्थी किसानों की कहानियों की जानकारी दी जाएगी, ताकि फसल बीमा की लाभ से कोई भी कृषक वंचित न रहे एवं अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सकें।
- दोनों बीमा योजना से लाभ लेने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2022 है। इस बीमा रथ के माध्यम से किसानों से तय तिथि तक फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की जाएगी।

नोट :

भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में दी 7 खेलो इंडिया सेंटर की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

1 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत सात खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंज़ूरी दी गई है। ये सातों केंद्र अलग-अलग ज़िलों में एक-एक खेल के लिये खोले जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा वेटलिफ्टिंग, फुटबाल, खो-खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिये खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी दी गई है। इन केंद्रों की स्थापना के लिये भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा।
- इन सात केंद्रों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या 14 हो गई है।
- मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में सात खेलो इंडिया केंद्र की मंजूरी मिलने पर कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह 'खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खेल संचालनालय ने विभिन्न खेलों की खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसमें से बालोद में वेटलिफ्टिंग सेंटर, बलौदाबाज़ार में फुटबाल सेंटर, पाटन दुर्ग में कबड्डी सेंटर, कांकेर में खो-खों सेंटर, रायपुर में वेटलिफ्टिंग सेंटर, रायगढ़ में बैडमिंटन सेंटर और सुकमा में फुटबाल सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त की गई है।
- इससे पहले शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी सेंटर, बीजापुर में तीरंदाजी सेंटर, राजनांदगाँव में हॉकी सेंटर, जशपुर में हॉकी सेंटर, गरियाबंद में व्हॉलीबॉल सेंटर, नारायणपुर में मलखंभ सेंटर और अंबिकापुर सरगुजा में फुटबॉल खेल की खेलो इंडिया सेंटर प्रारंभ करने की स्वीकृति भारतीय खेल प्राधिकरण से प्राप्त हो चुकी है।
- इन सभी खेलो इंडिया सेंटर्स को प्रारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ खेल संचालनालय द्वारा लगातार इन सेंटर्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक खेल के स्थानीय सीनियर खिलाड़ियों को सेंटर से जोड़ा जाएगा, उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिये मानदेय भी दिया जाएगा।
- सभी खेलो इंडिया सेंटर्स में बालक एवं बालिका खिलाड़ियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित की जाएगी। इन सेंटर्स को भारतीय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोज़गारी

चर्चा में क्यों ?

2 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा बेरोज़गारी दर के संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवंबर माह में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में 0.1 फीसदी के साथ छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है।

प्रमुख बिंदु

- सीएमआईई द्वारा 1 दिसंबर को जारी ताजा आँकड़ों के अनुसार नवंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर 1 फीसदी दर्ज की गई है, जबकि नवंबर माह में देश में बेरोज़गारी दर का यह आँकड़ा 8.2 फीसदी रहा है।
- छत्तीसगढ़ 1 प्रतिशत बेरोज़गारी की दर के साथ लगातार देश का न्यूनतम बेरोज़गारी दर वाला राज्य बना हुआ है।
- गौरतलब है कि सीएमआईई के मई-अगस्त 2018 में जारी किये गए आँकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोज़गारी दर 22 प्रतिशत थी। राज्य शासन की योजनाओं से इसमें उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बेरोज़गारी की दर छत्तीसगढ़ में माह दिसंबर 2022 में घटकर 0.1 प्रतिशत रह गई है।
- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी ताजा आँकड़ों से यह साबित हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 90 फीसद लोग किसी न किसी रोज़गार से जुड़कर आजीविका हासिल कर रहे हैं।

नोट :

- नवंबर माह में देश के शहरी क्षेत्रों में 0 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गारी का आँकड़ा 7.8 फीसद रहा है।
- न्यूनतम बेरोज़गारी दर के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को मिली इस उपलब्धि के पीछे वजह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोज़गार के नए अवसरों के सृजन के लिये बनाई गई योजना और नीतियाँ रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीते पौने चार साल के भीतर अनेक ऐसे नवाचार हुए हैं, जिनसे शहर से लेकर गाँव तक हर हाथ को काम मिला है।
- सीएमआईई द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 में सबसे कम बेरोज़गारी दर वाले राज्यों में 1 फीसदी के साथ छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है। वहीं इसी अवधि में 1.2 फीसदी के साथ उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। ओड़िसा 1.6 फीसदी बेरोज़गारी दर के साथ तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में यह आँकड़ा 6.2 प्रतिशत है और गुजरात में 2.5 प्रतिशत रहा है।
- दूसरी ओर नवंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोज़गारी दर के मामले में हरियाणा शीर्ष पर है, जहाँ 6 फीसदी बेरोज़गारी दर दर्ज की गई है। जम्मू एवं कश्मीर में बेरोज़गारी दर 23.9 फीसदी दर्ज की गई।
- छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समावेशी विकास के लक्ष्य के साथ काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के साथ गाँवों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में नवाचार किये गए। इसमें 'सुराजी गाँव योजना'के अंतर्गत 'नरवा-गरूवा-घुरवा-बाड़ी'कार्यक्रम ने महती भूमिका निभाई तो दूसरी ओर 'गोधन न्याय योजना'के साथ गौठानों को रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पर विकसित किया गया, जिससे गोबर बेचने से लेकर गोबर के उत्पाद बनाकर ग्रामीणों को रोज़गार मिला। रोज़गार के नए अवसर सृजित हुए।
- 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इन लघु वनोपजों का प्रसंस्करण व मूल्य-संवर्धन किया गया। इससे वनांचल में भी लोगों को रोज़गार मिला। इसी तरह स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिये सी-मार्ट प्रारंभ किये गए हैं।
- 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना'से किसानों की आर्थिक समृद्धि की दिशा में प्रयास हुए तो वहीं इस योजना से उत्साहित किसानों की दिलचस्पी कृषि की ओर बढ़ी। राज्य में खेती का रकबा और उत्पादन बढ़ा।
- 'राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मज़दूर योजना'के तहत 'पौनी-पसारी'व्यवस्था से जुड़े लोगों को आर्थिक सहायता मिली। राज्य में नई उद्योग नीति लागू की गई, जिसमें अनेक वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी के प्रावधान किये गए। इससे उद्यमिता विकास को गति मिली।

स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी ज़िला सुकमा देश में प्रथम

चर्चा में क्यों ?

2 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नीति आयोग द्वारा अक्टूबर माह की जारी आकांक्षी ज़िलों की डेल्टा रैंकिंग में सुकमा ज़िले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

प्रमुख बिंदु

- आकांक्षी ज़िला सुकमा को अक्टूबर माह के लिये स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश में प्रथम रैंक मिला है।
- गौरतलब है कि प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों से ज़िले में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी मापदंडों में स्थिति बेहतर हुई है। ज़िले में गर्भवती महिलाओं की एएनसी रजिस्ट्रेशन में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं संस्थागत प्रसव में ज़िले में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वर्तमान स्थिति में 90 प्रतिशत संस्थागत प्रसव किये जा रहे हैं।
- उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ज़िले के आंगनबाड़ियों में गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करने की दर 14 प्रतिशत है। इसी तरह ज़िले में टीबी के मरीजों की पहचान में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं टीबी मरीजों के सफल इलाज में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ज़िला प्रशासन द्वारा ज़िले में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, मूलभूत सुविधाओं के विकास, कौशल विकास, जल संसाधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप नीति आयोग द्वारा जारी आँकड़ों के आधार पर अक्टूबर माह के ओवरऑल रैंक में सुकमा ज़िला को तीसरा स्थान मिला है, जो कि ज़िले में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी किये जा रहे बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया बिलासपुर एवं अंबिकापुर में रीजनल सी-मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

2 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय से बिलासपुर एवं अंबिकापुर में रीजनल सी-मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 863 संग्राहक परिवारों को 13 करोड़ 46 लाख 35 हज़ार रुपए की सहायता अनुदान राशि एवं छात्रवृत्ति योजनांतर्गत 7566 छात्र-छात्राओं को 8 करोड़ 4 लाख 65 हज़ार रुपए की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 28 ज़िलों में सी-मार्ट बन गए हैं। अब उत्पादों की बिक्री की समस्या नहीं है। सी-मार्ट से उपभोक्ताओं और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को आसानी हो गई है। समूह की महिलाओं की आय भी बढ़ रही है।
- उन्होंने कहा कि उन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा करें, जिनकी मार्केट में ज्यादा मांग है। नया उत्पाद बनाने से पूर्व उसका बाज़ार में मांग कैसी होगी, इसका आकलन बेहतर तरीके से कर लें।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि आज स्व-सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों को सी-मार्ट के माध्यम से एक बाज़ार मिला है। इससे उनकी आमदनी में वृद्धि होने के साथ ही रोज़गार भी बढ़ा है।
- उन्होंने कहा कि एक सी-मार्ट दूसरे ज़िले के या संभाग के सी-मार्ट से ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिससे किस सी-मार्ट में कौन-कौन से उत्पाद हैं, इसकी जानकारी मिल जाती है।
- मुख्यमंत्री बघेल ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के हितग्राहियों से सहानुभूतिपूर्वक बात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से कम समय में ही पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिल रही है। इससे उनके परिवार को एक आर्थिक संबल मिला है।
- मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेधावी छात्र-छात्राओं को मिलने वाली इस राशि से उनकी आगे की पढ़ाई में काफी सहायता मिलती है और भी अन्य छात्र-छात्राओं को पूरी मेहनत से पढ़ाई करने के लिये प्रोत्साहन मिलता है।

बुजुर्गों, दिव्यांगजन और तृतीय लिंग समुदाय के लिये हेल्पलाईन सुविधा शुरू

चर्चा में क्यों ?

3 दिसंबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को आपात् कालीन स्थिति में जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई नई हेल्पलाइन सुविधा का विधिवत् शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

इस सुविधा के जरिये मेडिकल सहायता, पेंशन के साथ ही विभिन्न योजनाओं में आ रही दिक्कतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। इस नई हेल्पलाइन सुविधा का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस से बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिये हेल्पलाईन नंबर 155326 और टोल फ्री नंबर- 1800-233-8989 की सुविधा शुरू करने की घोषणा की थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा इस सुविधा का संचालन प्रायोगिक तौर पर किया जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर इसका विधिवत् शुभारंभ हुआ है।
- इस नई सुविधा से महतारी एक्सप्रेस-102, मेडिकल हेल्पलाइन 104 और आपात् कालीन सेवाओं के लिये जारी नंबर 112 को भी जोड़ा गया है। इससे बुजुर्ग, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हों और जिनकी संतानें प्रदेश के बाहर कार्यरत हैं, उनके लिये आपात् स्थितियों में सहायता के लिये प्रदेश में कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिये एक नवंबर (राज्य निर्माण दिवस) से सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी।

नोट :

- समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और उभयलिंग व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिये कई योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। हेल्पलाईन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आपात्कालीन सेवाएँ, परामर्श, शिकायत, पेंशन भुगतान के निराकरण संबंधी अनेक कार्यों के लिये मदद ली जा सकती है।
- इस अवसर पर महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर हर वर्ष लगभग 10 हज़ार दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल सहित अन्य पुनर्वास उपकरण वितरित किये जाएंगे। इसी प्रकार 15 हज़ार दिव्यांगजनों को उनके रूचि के मुताबिक रोज़गार से जोड़ने के लिये कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें 5-5 हज़ार अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित और मुक बधिर दिव्यांगजनों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देने की कार्ययोजना बनाई गई है।

राजस्व मंत्री ने किया राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने कोरबा निवास पर वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार दुबे द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- लगभग 1100 पृष्ठों के इस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोक हित में भू-राजस्व संहिता में जितने संशोधन किये गए हैं तथा इन संशोधनों के प्रवर्तन के लिये राज्य सरकार द्वारा शासकीय परिपत्रों के माध्यम से जो दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, उन सभी का समावेश किया गया है।
- राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ के लोकार्पण अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि इस ग्रंथ में राजस्व संबंधी सभी संदर्भों का समावेश होने से राजस्व प्रकरणों के संबंध में यह ग्रंथ मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हुए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इस ग्रंथ से राजस्व न्यायालयों और अधिवक्ताओं को बहुत सहायता मिलेगी।
- राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ के लेखक विजय कुमार दुबे ने बताया कि ग्रंथ में राजस्व संबंधी मामलों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किये गए अद्यतन परिपत्रों तक को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ग्रंथ राजस्व संबंधी प्रकरणों के निपटान में एक संदर्भ पुस्तक के रूप में सर्व संबंधित के लिये बहुत उपयोगी साबित होगा।
- विजय कुमार दुबे ने बताया कि उनके द्वारा लिखित अनेक पुस्तकों में से यह चौथी पुस्तक है, जिसका विमोचन राजस्व मंत्री द्वारा किया गया है। इससे पूर्व तीन अन्य पुस्तकों का विमोचन विगत वर्षों में राजस्व मंत्री द्वारा किया गया है।

मुख्यमंत्री ने देवभोग में लघु वनोपज उत्पाद पार्क का भूमिपूजन किया

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरियाबंद ज़िले के सुदूर वनांचल क्षेत्र के विकासखंड मुख्यालय देवभोग के समीप गाँव 'इंदागाँव'में बन रहे लघु वनोपज पर आधारित ग्रामीण उद्यम पार्क का भूमिपूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- देवभोग में ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना का उद्देश्य इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए मूल्यवर्धन करना है। यह पार्क गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये उत्प्रेरक होगा।
- इस केंद्र में कुल 11 महिला स्व-सहायता समूह शामिल होंगे, जिसके अंतर्गत लगभग 150 महिलाएँ सीधे केंद्र से जुड़ेंगी एवं विकासखंड के अंतर्गत 16000 से अधिक संग्राहक परिवार उच्च आय प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकेंगे।
- गौरतलब है कि इंदागाँव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बहुतायत मात्रा में लघु वनोपज, जैसे- महुआ फूल सूखा, चिरौंजी गुठली, दाल, महुआ बीज, लाख इत्यादि वनोपज पाये जाते हैं।
- ग्रामीण उद्यम पार्क देवभोग में प्रस्तावित प्रसंस्करण इकाई हैं- चिरौंजी प्रसंस्करण, लाख प्रसंस्करण, दाल प्रसंस्करण, नीम, महुआ एवं कुसुम तेल प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण इकाई।

नोट :

- छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम मर्या. रायपुर द्वारा ग्रामीण उद्यम पार्क की स्थापना 42 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। सचिव, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नई दिल्ली से 3.75 करोड़ रुपए, ग्रामीण उद्यम पार्क से 2.00 करोड़ रुपए तथा शेष 1.67 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, ज़िला वनोपज सहकारी संघ एवं वनधन विकास केंद्र से प्रदान किये जाएंगे।
- यह परियोजना देवभोग क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगी, जो किसी भी कुटीर उद्योग, प्रसंस्करण केंद्र से रहित रहा है।
- यह परियोजना छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और गरियाबंद ज़िले की पहचान बनाने के लिये पूरे देश में कृषि-वन उपज का विपणन सुनिश्चित करते हुए ब्लॉक में बड़ा बदलाव ला सकती है।

सरायपाली का शिशुपाल पहाड़ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद ज़िले के सरायपाली में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वहाँ के प्रसिद्ध शिशुपाल पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री की घोषणा से अब इस पहाड़ पर ट्रैकिंग, पर्यटकों के लिये कई मूलभूत सुविधाओं को स्थापित करने का रास्ता खुल गया है। अंग्रेजों के जमाने से इलाके की पहचान रहे इस पहाड़ को पर्यटन के लिये विकसित करने से सरायपाली को नई पहचान मिलेगी।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सरायपाली में अंतरराज्यीय बस स्टैंड और क्षेत्र में नल-जल योजना की घोषणा की।
- छत्तीसगढ़ में पर्यटन से स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने की नीति से यहाँ के युवाओं के लिये आमदनी के नए अवसर बनेंगे। राज्य ही नहीं दूसरे प्रदेशों से भी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति और रीति-रिवाजों से लोगों को अवगत कराने का मौका मिलेगा।
- ऐसी मान्यता है कि शिशुपाल पहाड़ के ऊपर किसी समय राजा शिशुपाल का महल हुआ करता था। जब राजा को अंग्रेजों ने घेर लिया तब राजा ने अपने घोड़े की आँख पर पट्टी बांधकर पहाड़ से छलांग लगा दी थी। इसी कारण इस पहाड़ को शिशुपाल पर्वत और यहाँ के झरने को घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है।
- राजधानी रायपुर से करीब 157 किमी. और सरायपाली से 30 किमी. की दूरी पर शिशुपाल पर्वत स्थित है। समुद्र तल से शिशुपाल पर्वत की ऊँचाई करीब 900 फीट है। शिशुपाल पर्वत के ऊपर पहुँचने पर बड़ा सा मैदान है, जहाँ से बारिश के दिनों में पानी घोड़ाधार जलप्रपात के रूप में करीब 1100 फीट नीचे गिरता है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित बलौदा थाने का लोकार्पण किया। बलौदा पुलिस चौकी पहले सरायपाली थाने के अंतर्गत थी। इस चौकी के पुलिस थाना के रूप में उन्नयन से आस-पास के 60 गाँवों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में 57वीं किस्त का ऑनलाईन अंतरण किया

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को योजना की 57वीं किस्त के रूप में 7 करोड़ 83 लाख रुपए का ऑनलाईन भुगतान किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत 16 नवंबर से 30 नवंबर तक गौठानों में गोबर विक्रेता पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किये गए गोबर के एवज में उनके खाते में 4.62 करोड़ रुपए की राशि ऑन लाईन अंतरित की गई। इसी प्रकार गौठान समितियों को 1.28 करोड़ रुपए तथा महिला समूहों के खाते में 1.93 करोड़ रुपए की लाभांश राशि अंतरित की गई।
- गोबर विक्रेताओं को भुगतान की गई 4.62 करोड़ रुपए की राशि में से 4270 स्वावलंबी गौठानों द्वारा 2.88 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया तथा कृषि विभाग द्वारा 1.74 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

नोट :

- पिछले पखवाड़े में गोबर खरीदी के लिये प्रदेश के स्वावलंबी गौठनों ने कृषि विभाग की तुलना में अधिक राशि का भुगतान किया है। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक अपने संसाधनों से 29.61 करोड़ रुपए की राशि से गोबर की खरीदी की गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गौठानों द्वारा खुद की जमा पूंजी से गोबर खरीदना गोधन न्याय योजना की बड़ी सफलता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के आधे से अधिक गौठान स्वयं के संसाधनों से गोबर की खरीदी कर रहे हैं। राज्य शासन को इन गौठानों को गोबर खरीदने के लिये राशि देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'में प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। गौठानों में विकसित किये जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की गतिविधियों में युवाओं और महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। इससे युवाओं और महिलाओं को रोज़गार और आमदनी का अच्छा जरिया मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में किसान स्वयं पैरादान कर रहे हैं। पैरादान के लिये किसानों को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। जब गौठानों में पशुओं के लिये चारा और पानी की व्यवस्था होगी, तो पशु खेत और सड़कों के बजाय गौठानों में रहेंगे। उन्होंने प्रदेश के अधिक से अधिक गौठानों में पैरा के बंडल बनाने के लिये बेलर मशीन उपलब्ध कराने का प्रयास करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में ऐसे उत्पाद प्राथमिकता के आधार पर तैयार किये जाएँ, जिनकी शासन को ज़रूरत है या जिनकी मार्केट में अच्छी मांग है। उन्होंने कहा कि अच्छे उत्पादों को तैयार करने के लिये युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।
- कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में 11 हज़ार 252 गौठानों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 9 हज़ार 619 गौठान निर्मित किये गए हैं, इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 8440 गौठान निर्मित किये गए हैं। इन गौठानों में से 4270 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं।
- गोबर खरीदी, वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन और वितरण का काम विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। आने वाले समय में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन छत्तीसगढ़ में एक बड़ा अभियान बनेगा। उन्होंने कहा कि रीपा की गतिविधियाँ से युवाओं को जोड़कर और अधिक बढ़ाया जाएगा।
- गोधन न्याय मिशन के प्रबंध संचालक डॉ. अय्याज़ तंबोली ने बताया कि गोबर खरीदी के एवज में गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद से अब तक 188.45 करोड़ रुपए तथा गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि के रूप में 170.05 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
- उन्होंने बताया कि अब तक गौठानों में 19.82 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है। इसमें से 16.24 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का विक्रय किया जा चुका है। गौठानों में अब तक पैरादान से 2.25 लाख क्विंटल पैरा मिला है।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को किया जाएगा सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 10-11 दिसंबर को बनारस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन के लिये दिसंबर 2022 तक के लिये निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया है।
- छत्तीसगढ़ को कुल 4825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानि 4887 केंद्रों का संचालन हो रहा है।
- प्रदेशवासियों को सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) नियुक्त किये गए हैं।
- इन केंद्रों में प्रसव पूर्व देखभाल व प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संचारी रोग व गैर-संचारी रोग स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, सामान्य रोगों के लिये बाह्य रोगी देखभाल एवं प्रबंधन, आँख-नाक-कान-गला संबंधी सामान्य देखभाल, मुख स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराई जा रही हैं।

नोट :

- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में 30 साल से अधिक उम्र के लोगों के रक्तचाप, डायबिटीज व कैंसर जैसी बीमारियों की निःशुल्क जाँच भी की जाती है। इनके मरीजों को ज़रूरत के अनुसार निःशुल्क दवा और परामर्श भी दिया जाता है।
- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में उपचार के साथ-साथ लोगों को स्वस्थ जीवन-शैली के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिये इन केंद्रों के माध्यम से योग एवं वेलनेस की गतिविधियाँ भी संचालित की जा रही हैं।
- इन सेंटर्स में गाँव में ही इलाज मिलने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भीड़ कम हुई है। इससे मरीजों को इलाज के लिये ज्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ रही है। किसी व्यक्ति में गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर उसे समय रहते जानकारी दे दी जाती है जिससे वह समय पर अपना इलाज करा सके।
- स्वास्थ्य विभाग जरूरत की सभी दवाईयाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहा है ताकि प्राथमिक व नियमित तौर पर चलने वाला उपचार गाँव में ही संभव हो सके।

जी-20 समूह की बैठक अगले साल छत्तीसगढ़ में होगी

चर्चा में क्यों ?

9 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जी-20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जी-20 समूह की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की बैठक देश के अलग-अलग राज्यों और प्रदेश में कराने की बात कही थी, ताकि समूह के दूसरे देश भारत की संस्कृति और लोककला से परिचित हों।
- प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता की तैयारी को लेकर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके सहित सभी राज्यों के राज्यपाल, उप राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शामिल हुए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जी-20 की अध्यक्षता करने का भारत को उत्कृष्ट अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें सभी राज्यों को अपनी कला, संस्कृति एवं अपनी विशिष्टता दिखाने का अवसर मिलेगा।
- उन्होंने कहा कि जी-20 देशों के एक लाख से भी अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, देश के विभिन्न राज्यों में बैठकों, सम्मेलनों में शामिल होंगे। इसके लिये सभी राज्यों को अपनी ओर से कुछ नये कार्यक्रम भी जोड़ना चाहिये। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं स्कूली विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों को भी जी-20 के कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिये।
- उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किये गए विकास के कार्यों को विशेष रूप से प्रदर्शित करना चाहिये।
- उल्लेखनीय है कि भारत की अध्यक्षता में जी-20 का 18वाँ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में अगले वर्ष 2023 में आयोजित होगा। यह सम्मेलन 'वसुधैव कुटुम्बकम'के आदर्श पर आयोजित किया जाएगा। 09 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तथा भारत के सभी राज्यों के कुल 56 स्थानों पर 215 बैठकें होंगी, जिनमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

10 दिसंबर, 2022 को शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने तीन दिवसीय राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में 10 से 12 दिसंबर तक आयोजित तीन दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता के प्रथम दिन 150 प्रतिभागी शामिल हुए।

नोट :

- राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता 2 विधाओं - केनवास में पेंटिंग एवं ड्राइंग शीट पेंटिंग में आयोजित की गई है। केनवास पेंटिंग की प्रतियोगिता में दो आयु वर्ग 16 से 25 एवं 25 आयु वर्ग से ऊपर के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रकार ड्राइंग शीट पेंटिंग में 12 से 18 आयु वर्ग और 18-30 आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल हुए।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि प्रतियोगिता के प्रत्येक विधा एवं आयु वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया जाएगा।
- केनवास पेंटिंग 16 से 25 आयु वर्ग एवं 25 से अधिक के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 11 हज़ार, द्वितीय को 8 हज़ार एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 6 हज़ार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी।
- इसी प्रकार ड्राइंग शीट पेंटिंग 12 से 18 आयु वर्ग और 18-30 आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 5 हज़ार, द्वितीय को 3 हजार एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2 हज़ार रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी।
- इसके अलावा प्रत्येक आयु वर्ग के 5 प्रतिभागियों को 1 हज़ार रुपए के मान सांत्वना पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

10 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ को समय-सीमा के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल करने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिये सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में आयोजित कार्यक्रम में इस उपलब्धि के लिये छत्तीसगढ़ को प्रमाण-पत्र प्रदान किया।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉ. पूनम सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ की ओर से बनारस में यह सम्मान ग्रहण किया।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन के लिये दिसंबर 2022 तक के लिये निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया है। छत्तीसगढ़ को कुल 4825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के रूप में संचालित करने का लक्ष्य मिला था। राज्य में अभी इस लक्ष्य से 62 अधिक यानि 4887 केंद्रों का संचालन हो रहा है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को इस उत्कृष्ट कार्य व उपलब्धि के लिये बधाई बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में जल्दी ही सभी चयनित स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन कर लिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लोगों को प्रसव पूर्व देखभाल व प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं संचारी रोग व गैर-संचारी रोग स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन, सामान्य रोगों के लिये बाह्य रोगी देखभाल एवं प्रबंधन, आँख-नाक-कान-गला संबंधी सामान्य देखभाल, मुख स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, वयोवृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराई जा रही हैं।
- लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने इन केंद्रों के माध्यम से योग एवं वेलनेस की गतिविधियाँ भी संचालित की जा रही हैं। प्रदेशवासियों को सार्वभौमिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) नियुक्त किये गए हैं।

नोट :

राज्य भर में मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 दिसंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री जनता के नाम संदेश भी देंगे।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, वनमंडल अधिकारियों एवं सहकारिता विभाग सहित इन आयोजनों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें गौरव दिवस के आयोजन के संबंध में जरूरी निर्देश दिये।
- गौरव दिवस के दिन सभी ज़िलों के गौठानों, सहकारी सोसायटी परिसरों, धान खरीदी केंद्रों, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों, वनोपज प्रबंधन समितियों के कार्यालय स्थलों, हाट-बाज़ारों, नगरीय निकायों के वार्डों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों, निर्णयों के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियाँ दी जाएंगी।
- गौरव दिवस के दिन सुबह 11 बजे से राज्य के सभी गौठानों, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों, नगरीय क्षेत्रों के प्रत्येक वार्डों और दोपहर 3 बजे से प्राथमिक सहकारी सोसायटी परिसर और धान खरीदी केंद्रों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
- गौठान में आयोजित कार्यक्रम में गौठान समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, पशुपालक, गाँव के किसान, भूमिहीन मजदूर, जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकायों के सदस्य, राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य सहित स्थानीय निवासी हिस्सा लेंगे।
- नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक हिस्सा लेंगे।
- वन क्षेत्रों में तेंदुपत्ता संग्रहण केन्द्रों और हाट बाज़ारों में भी गौरव दिवस का आयोजन होगा। तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों में गौरव दिवस के दिन किसानों और मजदूरों के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी देने के साथ हाट बाज़ारों में सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी।
- इसी प्रकार प्राथमिक सहकारी सोसायटियों और धान खरीदी केंद्रों पर किसानों को आमंत्रित करके शासन की कृषि संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे कि ब्याज मुक्त ऋण योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इत्यादि की जानकारी उन्हें दी जाएगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यों का संचालन अब समग्र शिक्षा से

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में संचालित नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (शिक्षा का अधिकार) योजना का संचालन अब समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अभी तक यह योजना लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालित की जा रही थी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के अधिकार योजना के तहत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों का दावा निपटारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड से किये जाने और योजना के समस्त कार्य, प्रबंधन का दायित्व संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के स्थान पर प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को सौंपा गया है।
- उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 की योजना भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्र द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के फंड विमुक्त करने और उनके उपयोग के निगरानी की संशोधित प्रक्रिया निर्धारित है।

नोट :

- विभागीय आदेश द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत इस योजना में सिंगल नोडल एजेंसी और योजना के नोडल अधिकारी समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया है।
- योजना के समस्त दायित्व, निर्वहन एवं जिम्मेदारी के लिये समग्र शिक्षा निर्धारित है। वर्तमान में यह कार्य संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला में छत्तीसगढ़ को एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (ePMSMA) को लागू करने में देश में दूसरे स्थान पर रहने के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम की संयुक्त संचालक डॉ. अल्का गुप्ता, रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शैलेंद्र अग्रवाल और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा ने प्रदेश की ओर से नई दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- विदित है कि राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल माह से नवंबर माह के बीच एक लाख 48 हजार 851 गर्भवती महिलाओं की एएनसी जाँच की गई है।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदेश में हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की एएनसी जाँच की जाती है। एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब हर महीने 9 तारीख के अलावा 24 तारीख को भी एएनसी जाँच की जा रही है।
- मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शैलेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कार्यशाला में छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग गाइडलाइन पर पोस्टर प्रस्तुत किया गया। पोस्टर के माध्यम से हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जल्द से जल्द पहचान कर उपचार कैसे किया जाता है, यह बताया गया।

मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवर ब्रिज का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

15 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान महासमुंद ज़िले में महासमुंद-तुमगाँव रोड के रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- बहुप्रतीक्षित तुमगाँव ओवरब्रिज के बन जाने से शहर-वासियों को लगातार लगने वाले ट्रेफिक जाम व आने जाने में होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल जाएगा।
- ज़िले की जनता खासकर तुमगाँव और महासमुंद की ओर से रोज आने-जाने वाली जनता को सरल, सुगम मार्ग मिलेगा। वर्तमान में रेलवे फाटक बंद होने के कारण जाम की स्थित बन जाती थी। रेलवे ओवरब्रिज बन जाने से उन्हें इससे निजात मिलेगी और समय की भी बचत होगी।
- गौरतलब है कि तुमगाँव रेलवे ओवरब्रिज बन जाने से महासमुंद की लगभग 35 हज़ार से ज्यादा की आबादी को सुविधा मिलेगी।
- ओवरब्रिज की कुल लंबाई 616 मीटर एवं चौड़ाई 15 मीटर है। रेलवे क्रॉसिंग से महासमुंद की ओर 294 मीटर एवं तुमगाँव की ओर 248 मीटर एवं रेलवे क्रॉसिंग की लंबाई 74 मीटर है।
- इसके अलावा महासमुंद ज़िले में मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात के दौरान पटेवा और तुमगाँव में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, तुमगाँव में तहसील की स्थापना करने सहित कई अन्य घोषणाएँ भी की।

नोट :

'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'

चर्चा में क्यों ?

17 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'लागू किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय व रोज़गार के अवसर को बढ़ाना है।
- मुख्यमंत्री ने राज्य में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के संबंध में 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
- मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा'की घोषणा करते हुए इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
- इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी शालाओं, छात्रावासों, आश्रमों, शासकीय भवनों के रखरखाव और उन्नयन के लिये 1000 करोड़ रुपए एवं तकनीकी शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिये 'स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट आईटीआई योजना'की घोषणा करते हुए इस योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने 'न्याय के चार साल'एवं 'न्याय के रास्ते-सबके वास्ते' पुस्तकों का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

17 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के अवसर पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जन संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित दो पुस्तकों 'न्याय के चार साल'एवं 'न्याय के रास्ते-सबके वास्ते'का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- 'न्याय के चार साल' पुस्तक राज्य सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों और जनहितकारी फैसलों पर केंद्रित है। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना के साथ अन्य जन-कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी शामिल है।
- इसी प्रकार 'न्याय के रास्ते-सबके वास्ते'पुस्तक शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पर केंद्रित है। इस पुस्तक में योजना का नाम, उद्देश्य, शर्त, पात्रता, प्रावधान एवं संपर्क सूत्र की जानकारी दी गई है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के न्याय के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जन-संपर्क विभाग द्वारा इन पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है, ताकि लोगों को शासन के सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी हो तथा वे उनका लाभ उठाकर अपने जीवन-स्तर को बेहतर बना सकें।

छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने मध्य प्रदेश से लाए जाएंगे बाघ

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिये मध्य प्रदेश से बाघ लाए जाने सहित कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रस्ताव के अनुसार मध्य प्रदेश से से लाये गए बाघों को अचानकमार टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही साथ बारनवापारा अभयारण्य में भी बाघों के लिये अनुकूल परिस्थितियों के चलते टाइगर छोड़े जाएंगे।
- छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में इसके साथ ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण, वन्य प्राणी मानव द्वंद रोकने के अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये वनों की 10 किलोमीटर की परिधि के गांवों में आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने, वन्य प्राणियों की सुरक्षा की दृष्टि से वन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने, हाथी मानव द्वंद रोकने जागरूकता अभियान को गति देने और वन्य प्राणियों के लिये पानी और चारागाह विकसित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में इनसे संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या चार गुना करने के लिये ग्लोबल टाइगर फोरम (जीटीएफ) द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, जिसके क्रियान्वयन की अनुमति बैठक में दी गई। जिसके तहत अचानकमार टाइगर रिजर्व में बाघ मध्य प्रदेश से लाकर छोड़े जाएंगे।
- अधिकारियों ने बताया कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणियों के लिये जल स्त्रोतों, चारागाह को विकसित किया गया है, जिससे शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या में वृद्धि हो सके।
- बोर्ड की बैठक में बलौदाबाजार ज़िले के बारनवापारा अभयारण्य में फिर से टायगरों को पुनर्स्थापित करने के लिये टाइगर छोड़ने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक सहमति दी गई।
- बारनवापारा अभयारण्य में वर्ष 2010 तक टाइगर पाए जाते थे। टाइगर रि-इंट्रोडक्शन एवं टाइगर रिकव्हरी प्लान के तहत ख्याति प्राप्त वन्यप्राणी संस्थान से हैबिटेट सुटेबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी, जिसकी स्वीकृति राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त होने के बाद इस अभयारण्य में बाघ पुनर्स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
- अधिकारियों ने बैठक में बताया कि शाकाहारी वन्य प्राणियों को विभिन्न प्रजनन केंद्रों एवं अन्य स्थानों से लाकर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतिक रहवास में छोड़ा गया है।
- बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में हाथियों के लिये चारागाह, पानी आदि की व्यवस्था करने से हाथी मानव द्वंद की घटनाओं में काफी कमी हुई है। लगभग 11 हज़ार 314 हेक्टेयर चारागाह विकसित किए गए हैं। लगभग 80 हज़ार हेक्टेयर में खाद्य घास की प्रजातियां लगाई गई हैं।
- बैठक में भारत माला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिये उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में केशकाल एवं कांकेर वनमंडल के लगभग 64 वन क्षेत्र तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा चिन्हांकित इद्रांवती- उदंती-सीतानदी-सुनाबेड़ा टाइगर कॉरिडोर के 7 वन कक्षों से गुजरने वाले लगभग 3.5 किलोमीटर राजमार्ग में प्रस्तावित इकानॉमिक कॉरिडोर निर्माण के लिये अनुमति दी गई।
- इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाएगा। इस तरह भोपालपट्टनम से जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चिंतावागु नदी पर नवीन पुल निर्माण की अनुमति दी गई। यह प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को अनुमति के लिये भेजा जाएगा। इस नवीन पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण इद्रांवती टाइगर रिजर्व के बफर जोन के 1.177 हेक्टेयर रकबे के अंतर्गत आता है।
- बैठक में वन क्षेत्रों में बेहतर संचार की सुविधा के लिये ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल टॉवर लगाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इससे जहां वन प्राणी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। वहीं वन क्षेत्रों के गांवों में पीडीएस सिस्टम, धान खरीदी, वृद्धावस्था पेंशन, बैंकिंग और ऑनलाइन पढ़ाई में आसानी होगी।
- बैठक में वनभैंसों में कृत्रिम गर्भाधान करने की अनुमति भी प्रदान की गई। इस प्रस्ताव के अनुसार वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया तथा LaCONES, CCMB हैदराबाद के विशेषज्ञों एवं वन विभाग में पदस्थ पशु चिकित्सकों के देख-रेख में वीर्य निकालने का कार्य किया जाएगा तथा इस उपयोग मादा वनभैंसों के कृत्रिम गर्भाधान हेतु किया जाएगा।

राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी विशेष पुस्तक 'बैक फ्राम दी ब्रिंक' का विमोचन

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई विशेष पुस्तक 'बैक फ्राम दी ब्रिंक' (BACK FROM THE BRINK) का विमोचन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पिछले लगभग 17 वर्षों से डब्ल्यूटीआई, छत्तीसगढ़ वन विभाग के साथ वन भैंसों के संरक्षण एवं संवर्धन पर कार्य कर रहा है। इस पुस्तक में पिछले दो दशकों से चल रही परियोजना के विभिन्न पहलुओं के विवरण के साथ-साथ संरक्षण के लक्ष्य का विस्तृत विवरण दिया गया है।
- गौरतलब है कि भारत में विश्व स्तर पर लुप्तप्राय जंगली भैंसों (बुवालिस अरनी) की 80 प्रतिशत से अधिक संख्या पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में कठोर भूमि (हार्ड ग्राउंड) में वन भैंसों की संख्या 50 से भी कम रह गई है। असम की आर्द्र भूमि में वन भैंसों की संख्या 4000 के करीब है।
- वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक और कार्यकारी निर्देशक विवेक मेनन के अनुसार, डब्ल्यूटीआई ने 2005 में जब राज्य में कार्य करना शुरू किया, उस समय उदंती अभयारण्य में एक मादा वन भैंस के साथ सिर्फ छह वन भैंसे बचे थे। इसका मतलब यह था कि मध्य भारत की अलग-अलग आबादी के विलुप्त होने का गंभीर खतरा था।
- यह रिपोर्ट लुप्तप्राय वन भैंसों के साथ 15 वर्षों के संरक्षण कार्य का इतिहास है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु के संरक्षण के लिये वैश्विक ध्यान के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।
- वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उपनिदेशक एवं मध्य क्षेत्र प्रमुख डॉ. राजेंद्र मिश्रा के अनुसार परियोजना अवधि के दौरान उदंती अभयारण्य में अधिकतम 11 वन भैंसे थे। वन विभाग ने डब्ल्यूटीआई के तकनीकी सहयोग से वर्ष 2020 में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान से दो वन भैंसों (नर एवं मादा) कंजर्वेशन ब्रीडिंग के लिये बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने में भी सफलता प्राप्त की।
- पुस्तक में बताया गया है कि उदंती के वन भैंसे असम राज्य और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के जंगली भैसों के साथ हैप्लोटाइप साझा करती हैं और इसलिये उदंती में जंगली भैंसों की आबादी को बढ़ाने के लिये उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में घटते जा रहे वन एवं घास के मैदान जंगली भैंसों को बचाने में गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
- लगातार तीन वर्षों के जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, डब्ल्यूटीआई ने लगभग 4000 छात्रों, 3000 ग्रामीणों एवं 12 सार्वजनिक सेवा विभागों तक वन भैंसों के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रचार-प्रसार किया, जिसका असर समाज के सभी वर्गों तक पहुँचा है।

छत्तीसगढ़ के 'मोर मयारू गुरूजी' कार्यक्रम को मिला राष्ट्रीय सिल्वर स्कॉच अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्कॉच फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 'मोर मयारू गुरूजी' कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस सम्मान को महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और आयोग की अध्यक्ष तेजकुंवर नेताम ने प्राप्त किया।
- इस सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और वन विभाग बालोद को भी अवार्ड प्राप्त हुआ।
- सम्मान प्राप्त करने के उपरांत अपने उद्बोधन में अनिला भेड़िया ने कहा कि बच्चों की मानसिकता को देखकर-समझकर शिक्षकों को बच्चों से व्यवहार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि 7 चरणों की चरणबद्ध प्रक्रिया को पार करने के उपरांत ही प्राप्त होता है। यह अवार्ड महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में बाल संरक्षण के क्षेत्र में 'मोर मयारू गुरूजी 'कार्यक्रम के नवाचार पर दिया गया है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 'मोर मयारू गुरूजी' कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को बाल अधिकारों की रक्षा के लिये खेल एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है।
- आयोग द्वारा अब तक इस कार्यक्रम में विभिन्न ज़िलों एवं राज्य स्तर पर लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और भविष्य में इसे ज़िला स्तर तक विस्तार करने की भी योजना है।

नोट :

- इस कार्यक्रम को रोचक तरीके से डिजाईन किया गया है। इसकी अवधि मात्र 2 से 3 घंटे ही रखी गई है, जिससे शिक्षक इसे आसानी से ग्रहण कर सकें।
- आयोग का यह मानना है कि एक शिक्षक और बच्चे का संबंध 5 वर्ष से 12 वर्ष तक रहता है और इस बीच शिक्षक के व्यक्तित्व का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए बाल अधिकार सहित शिक्षकों द्वारा बच्चों से वार्तालाप करते समय और पढ़ाते समय किन बातों पर ज़ोर देना है और किन कमियों को सुधारना है, इन सभी विषयों को मोर मयारू गुरूजी कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

पुरातत्त्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा संस्कृति एवं राजभाषा का पृथक्-पृथक् संचालनालय

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने संस्कृति विभाग के अधीनस्थ संचालित संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग को पृथक्-पृथक् संचालनालय के रूप में घोषित कर दिया है। इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित संस्कृति विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- संस्कृति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग संचालनालय पुरातत्त्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के नाम से जाना जाएगा।
- नवगठित विभागाध्यक्ष कार्यालयों के सुव्यवस्थित कार्य निष्पादन-संचालन के लिये प्रशासनिक दृष्टि से कार्यालय का नाम एवं पता परिवर्तन किया गया है। इसके अनुसार संचालनालय पुरातत्त्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के कार्यालय का पता महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर सिविल लाइन रायपुर है।
- वहीं संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के कार्यालय का पता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यावसायिक परिसर द्वितीय तल सेक्टर-27 नवा रायपुर अटल नगर है।

अब होटलों के मेन्यू में शामिल होंगे मिलेट्स के बने व्यंजन

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के होटलों के मेन्यू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। इस संबंध में संयुक्त संचालक कृषि और राजधानी रायपुर के 64 होटल संचालकों के बीच बैठक हुई।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023 घोषित किया गया है, जिससे मिलेट्स के उत्पाद को जनसामान्य के दैनिक आहार में शामिल कर उपभोग को बढ़ावा देने हेतु प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
- इसी कड़ी में बीते दिनों कृषि विभाग की ओर से रायपुर क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, मार्ट के संचालकों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मिलेट उत्पाद के प्रचार-प्रसार के साथ प्रतिष्ठान के मेन्यू में मिलेट्स उत्पाद को शामिल करने का आग्रह किया गया। इससे ग्राहकों को मिलेट्स आधारित व्यंजन सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सकेगा।
- मिलेट्स में पाए जाने वाले पोषक तत्त्वों के फायदे की वजह से मिलेट्स का दैनिक आहार में उपभोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। इससे मिलेट्स फसल क्षेत्र वृद्धि व उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट संचालकों ने मिलेट्स आधारित व्यंजनों व उत्पादों को अपने प्रतिष्ठान के मेन्यू में शामिल करने का आश्वासन दिया।
- मिलेट्स में पोषक तत्त्वों की अधिकता के कारण इसे न्यूट्रीसीरियल्स भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, रेशा, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस आदि अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मिलेट्स में मुफ्त ग्लूकोज बहुत कम समय के लिये होता है, जो मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिये उपयुक्त आहार है।

नोट :

- मिलेट्स फसल में शामिल रागी में प्रोटीन व कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मज़बूत बनाने एवं कुपोषण दूर करने में सहायक हैं। रागी रेशा उदर विकार, उच्च रक्तचाप तथा आँतों के कैंसर से शरीर की रक्षा करता है।
- इसी तरह कुटकी में 37-38 प्रतिशत तक रेशा होता है, जो शिशु खाद्य पदार्थ, स्नैक्स एवं अन्य प्रंसस्कृत उत्पाद के लिये उपयोगी खाद्य घटक है। वहीं कोदो में प्रोटीन 11 एवं रेशा 14 प्रतिशत तक पाया जाता है, जो हृदय विकार, उच्च रक्तचाप तथा उच्च कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित लोगों के लिये उत्तम आहार है।
- उल्लेखनीय है कि मिलेट फसल के फसल क्षेत्र वृद्धि एवं उत्पादन बढ़ाने के साथ ही फसल के उपार्जन, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन करते हुए आमजन तक सुगमता से उत्पाद पहुँचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 'मिलेट मिशन' लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स फसलों में प्रमुख रूप से कोदो, कुटकी, रागी एवं ज्वार व बाजरा का उत्पादन किया जाता है।
- आँकड़ों पर नज़र डालें तो प्रदेश में उत्पादित कोदो, कुटकी एवं रागी का छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के माध्यम से वर्ष 2021 में 52,728 क्विंटल उपार्जन किया गया। वहीं वर्ष 2022-23 में 13 हज़ार टन मिलेट्स उपार्जन का लक्ष्य है।
- मिलेट्स से रागी खीर, लड्डू, माल्ट, केक, सेवईं, इडली, हलवा, पुलाव, कुटकी खीर, कुटकी चाय, जैम, कोदो खीर, ज्वार चॉकलेट, ब्राउनी आदि बनाए जाते हैं। कोदो व कुटकी को मुख्य भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है।

मुख्यमंत्री ने सोनाखान में ओपन एयर म्यूजियम और बलौदाबाज़ार-भाटापारा टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज़िला बलौदाबाज़ार-भाटापारा के सोनाखान में निर्मित भव्य ओपन एयर म्यूजियम और बलौदाबाज़ार-भाटापारा टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म एवं कर्मस्थली को उनके गौरव के अनुरूप विकसित करने के लिये ज़िला प्रशासन बलौदाबाज़ार-भाटापारा द्वारा सोनाखान में भव्य ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है।
- सोनाखान में बनाया गया यह म्यूजियम प्रदेश में अपनी तरह का पहला म्यूजियम होगा, जहाँ ऑडियो-विजुअल सेटअप और एक विशेष धातु कॉर्टेन स्टील के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को प्रदर्शित किया जा रहा है।
- सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शहीद वीर नारायण सिंह की गौरवगाथा को प्रदर्शित करने के लिये एक विशेष तरह की कॉर्टेन स्टील का प्रयोग किया गया है। कॉर्टेन स्टील एक तरह का ऐसा मेटल है, जिसमें पहले से ज़ंग की एक परत लगी हुई होती है। खास बात यह है कि यह धातु प्रकृति को हानि नहीं पहुँचाती। कुरूपाठ पहाड़ की हरियाली के बीच इसकी नयनाभिराम सुंदरता देखते ही बनती है।
- कॉर्टेन स्टील के बने लंबे और सुंदर पैनल्स पर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी उकेरी गई है, जिसकी भव्यता दिन के साथ ही रात में भी देखी जा सकती है। लाइट के अद्भुत सेटअप इसे खास और अलग बनाते हैं।
- सभी पैनल पर एक ऑडियो सेटअप लगा हुआ है, जिसके माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म से लेकर क्रांति और बलिदान की गाथा को सुना जा सकता है। यह ऑडियो हिन्दी, अंग्रेज़ी और छत्तीसगढ़ी भाषा में उपलब्ध है। यहाँ आने वाले लोग अपनी पसंद मुताबिक ऑडियो की भाषा तय कर सकते हैं।
- देश में कॉर्टेन स्टील का उपयोग विभिन्न महान परियोजनाओं में कलाकृतियाँ बनाने के लिये किया जा चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बिहार म्यूजियम और कई देशों के प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट में इसका उपयोग किया गया है।
- म्यूजियम में पार्किंग और केंटीन की भी व्यवस्था रहेगी। केंटीन की व्यवस्था स्व-सहायता समूह के द्वारा संचालित की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को म्यूजियम में प्रवेश सशुल्क रहेगा। इस नवाचार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी रोज़गार उपलब्ध होगा।

नोट :

- बलौदाबाज़ार-भाटापारा टूरिज्म सर्किट में बाबा गुरु घासीदास की जन्म एवं कर्मस्थली गिरौदपुरी, शहीद वीर नारायण सिंह की जन्म एवं कर्मस्थली सोनाखान, कबीर पंथियों की प्रसिद्ध धर्मस्थली दामाखेड़ा, तुरतुरिया, सिद्धखोल जलप्रपात, बलारडेम, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी और नारायणपुर का शिव मंदिर शामिल हैं। इस टूरिज्म सर्किट में आने वाले पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ ने 58 पदक लेकर पाँचवां स्थान प्राप्त किय

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को आंध्र प्रदेश के गुंटुर में संपन्न हुए तीसरे एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में कुल 58 पदक लेकर पाँचवां स्थान प्राप्त किया। इसमें 26 स्वर्ण, 12 रजत एवं 20 काँस्य पदक शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि आंध्र प्रदेश के गुंटुर में 17-22 दिसंबर तक एकलव्य राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस खेल महोत्सव में 22 राज्यों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकलव्य विद्यालयों से 288 बच्चे शामिल हुए।
- छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन एथलेटिक्स में किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 3 रजत, 4 काँस्य सहित कुल 20 पदक प्राप्त किये। वहीं तैराकी में 8 स्वर्ण, 6 रजत, 2 काँस्य सहित कुल 16 पदक तथा कुश्ती में 3 स्वर्ण, 2 रजत, 5 काँस्य सहित कुल 10 पदक प्राप्त किये।
- इसके अलावा शतरंज में 01 स्वर्ण, 02 काँस्य सहित 03 पदक, खो-खो (बालक) में 1 स्वर्ण, जूडो में 1 रजत, योगा में 2 काँस्य, बैडमिंटन, कबड्डी (बालक), हैंडबॉल (बालक) एवं खो-खो (कन्या) में 1 काँस्य तथा भारोत्तोलन में 1 रजत पदक प्राप्त किया।
- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ कांकेर के छात्र अर्जुन कोवाची ने 800 मीटर, 1500 मीटर एवं 4×400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक तथा 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया।
- इसी प्रकार एकलव्य तोकापाल बस्तर की सोनादायी कश्यप ने 400 मीटर, 200 मीटर एवं 100 मीटर में दौड़ में स्वर्ण पदक, एकलव्य छर्राटांगर रायगढ़ की भूमिका राठिया एवं एकलव्य पलारीखुर्द सक्ती की तानिया सिंह ने ऊँची कूद में स्वर्ण पदक जीता। तैराकी अंडर-14 में सोहन उराँव ने 03 स्वर्ण पदक प्राप्त किये।

करमा एथनिक रिसॉर्ट मैनपाट व जोहर मोटल का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

23 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, लोक निर्माण, गृह, जेल एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू के मुख्य आतिथ्य एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में मैनपाट के कमलेश्वरपुर में आयोजित समारोह में 'करमा एथनिक रिसॉर्ट'व 'जोहर मोटल' सोनतराई का लोकार्पण हुआ।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न थीमों पर आधारित पर्यटन विकास की 'स्वदेश दर्शन योजना'वर्ष 2015-16 में प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में यहाँ की आदिवासी/जनजातीय एवं ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को परिचित कराने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में 'ट्राइबल टूरिज्म सर्किट'की परियोजना स्वीकृत की गई। इस परियोजना में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के कुल 13 डेस्टीनेशन्स को विकसित किया गया है।
- इस परियोजना के 'ट्राइबल टूरिज्म सर्किट'के अंतर्गत कमलेश्वरपुर (मैनपाट) में 'ईको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन'के रूप में 'करमा एथनिक रिसॉर्ट'विकसित किया गया है। यह रिसॉर्ट सरगुजा क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश की थीम पर 21 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा इस परियोजना के लिये कमलेश्वरपुर में 46 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई थी।
- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत निर्मित करमा एथनिक रिसॉर्ट में पर्यटकों को ठहरने की सुविधा के साथ यहाँ की जनजातीय परंपरा, स्थानीय एवं तिब्बती संस्कृति को करीब से जानने-समझने का मौका मिलेगा।

नोट :

- 'करमा एथनिक रिसॉर्ट'कमलेश्वरपुर (मैनपाट) में टूरिस्ट रिसेप्शन एवं सुविधा केंद्र, 20 कक्ष (क्राफ्ट एवं हर्बल हाट-आर्टिसन सेंटर), कैफेटेरिया, ओपन एम्फीथिएटर, सोवेनियर शॉप, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, ट्राइबल वर्कशाप सेंटर, 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल (8 सीटर), इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, साइकल ट्रैक (प्रकाशीकरण सहित) समेत उच्चस्तरीय सुविधाएँ स्थापित की गई हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेंगी।
- 'सोनतराई मोटल, सीतापुर'में 5 कक्ष, डारमेटरी हॉल, लॉन, कैफेटेरिया (डायनिंग हॉल), स्टोर रूम, पार्किंग जैसी सुविधाओं का निर्माण किया गया है।
- इस योजना के परिचालन से मैनपाट में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, पर्यटकों को रुकने के लिये अन्य आवास सुविधा के साथ ग्रामीण परिवेश में रुकने का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होगा, स्थानीय लोगों को रोज़गार एवं आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध होंगे। यहाँ स्थानीय लोगों एवं हस्तशिल्प कलाकारों के साथ पर्यटकों को हस्तशिल्प प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
- इसके अलावा स्थानीय तिब्बतियन संस्कृति से भी पर्यटक परिचित होंगे, जिससे उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट्स का विक्रय बढ़ेगा, स्थानीय हस्तशिल्प, वनउपज/हर्बल प्रोडक्ट का विक्रय के लिये सोवेनियर शॉप्स में स्थान उपलब्ध होगा, व्यावसायिक दृष्टि से कॉन्फ्रेंस सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, मैनपाट में भविष्य में होमस्टे को बढ़ावा मिलेगा एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी।
- समारोह को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि करमा एथनिक रिसॉर्ट के शुरू होने से पर्यटक यहाँ रुकेंगे, जिससे मैनपाट में होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ के हस्तशिल्प को मार्केट मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने कहा कि मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मैनपाट प्रदेश के अन्य हिल स्टेशन से अलग है। यहाँ की 'जलजली' और 'उल्टा पानी'देश-दुनिया मे अनूठा है। प्रदेश में पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, रायपुर से उत्तर की ओर सतरेंगा, मैनपाट और जशपुर को जोड़ा जाएगा।

राज्यपाल ने वीर बाल दिवस के अवसर पर साहसी वीर बालक और बालिकाओं को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने वीर बाल दिवस के अवसर पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के साहसी वीर बालक और बालिकाओं को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के तत्त्वावधान में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन राजभवन में किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने सम्मानित चार बहादुर बालक-बालिकाओं को स्वेच्छा अनुदान मद से आर्थिक सहायता राशि प्रदाय करने की बात कही।
- वीर बाल दिवस के अवसर पर राजभवन में सम्मानित हुए चार बच्चों ने जो साहसिक कार्य किये हैं, वो अत्यंत प्रेरणादायी हैं। इन चार बच्चों में शामिल हैं- रायपुर ज़िले के टिकरापारा की रहने वाली 12 वर्षीय उन्नति शर्मा, दुर्ग ज़िले के 11 वर्षीय दुर्गेश सोनकर, बेमेतरा ज़िले के खमरिया क्षेत्र के बालक सीताराम यादव और कांकेर ज़िले के भानुप्रतापपुर की रहने वाली जंबावती भूआर्य।
- उल्लेखनीय है कि सिक्खों के दसवें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेहसिंह जी के द्वारा 26 दिसंबर को सिक्ख धर्म के गौरव की रक्षा के लिये क्रमशः 09 और 06 वर्ष की आयु में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया गया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जुझार सिंह और अजित सिंह ने भी धर्म की रक्षा में अपनी शहादत दी थी।
- छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी द्वारा गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदानी दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार के साथ सतत् पत्राचार किया गया। फलस्वरूप सिक्ख समुदाय के सम्मान स्वरूप वीर बाल दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई थी।

नोट :

छत्तीसगढ़ वन अधिकार क्रियान्वयन में देश में अग्रणी

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य देश में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार राज्य में विगत चार वर्षों में 54 हज़ार 518 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किये गए, जिसका कुल रकबा 30 हज़ार 46 हेक्टेयर है। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार के 23 हज़ार 982 वन अधिकार-पत्र वितरित किये गए हैं, जिसका कुल रकबा 11 लाख 77 हज़ार 212 हेक्टेयर है।
- देश में नगरीय क्षेत्र में वन अधिकारों की मान्यता दिए जाने में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। अब तक 266 व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र, 7 सामुदायिक वन अधिकार-पत्र और 4 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार-पत्र राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रदाय किये गए हैं।
- राज्य शासन द्वारा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी पहल की गई है। अब तक ज़िलों में 3 हज़ार 845 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य किये गए हैं। इसके अंतर्गत 16 लाख 60 हज़ार 301 हेक्टेयर भूमि के संरक्षण, प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को प्रदाय किया गया है।
- राज्य शासन द्वारा स्थानीय वन निवासी समुदायों के विभिन्न वनाधिकारों को मान्यता दिये जाने की दिशा में प्रतिबद्धतापूर्वक सतत् प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में वर्णित विभिन्न प्रकार के वनाधिकार उन्हें प्राप्त हो सके।
- अधिनियम के अनुसार वनभूमि पर अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्ज़े का दावा करने के लिये 13 दिसंबर, 2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक के मामले में कट ऑफ डेट पूर्व से ही तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से संबंधित ग्राम, वन भूमि में निवासरत होना आवश्यक है।
- राज्य शासन की पहल से स्थानीय वन निवासी समुदायों के लिये संबंधित ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को मान्यता दी जा रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य में विभिन्न कारणों से निरस्त वन अधिकार के दावों पर पुनर्विचार की कार्यवाही की जा रही है। वन अधिकार अधिनियम के तहत वितरित भूमि का रिकॉर्ड समय-समय पर दुरुस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
- वन अधिकार प्राप्त लाभार्थी को पोस्ट क्लेम सपोर्ट के रूप में उनकी कृषि को विकसित करने के साथ ही आजीविका के विभिन्न उपायों, जैसे- कुकून, टसरक्राप्स, लाख उत्पादन इत्यादि के माध्यम से लाभान्वित करने की दिशा में कार्य हो रहा है।
- छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियों को पर्यावास के अधिकार प्रदाय करने की कार्यवाही धमतरी ज़िले में शुरू की गई है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य करने की शुरुआत धमतरी ज़िले के जबर्रा गाँव से की गई। ग्राम सभा जबर्रा को 5352 हेक्टेयर वनभूमि पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई, जो देश में किसी एक गाँव को मान्य किये जाने वाला सर्वाधिक क्षेत्र है। इसी प्रकार कांकेर ज़िले के खैरखेड़ा ग्राम में 1861 हेक्टेयर वन भूमि पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की मान्यता दी गई है।
- वन अधिकार कानून के तहत प्रबंधन का बेहतर क्रियान्वयन करते हुए सामुदायिक वन संसाधन के तहत विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही हैं। जंगल के प्रबंधन के साथ-साथ बाँस का शेड एवं मचान बनाकर देशी बकरीपालन, मुर्गीपालन, खरगोशपालन, सुअरपालन, मछलीपालन आदि कार्य किया जा रहा है। साथ ही खरीफ फसल जैविक जिमीकंद, हल्दी बीज का उपचार कर तकनीकी विधि इंटरक्रॉपिंग से बुआई की जा रही है और बीज बैंक की स्थापना भी की गई है। इसके उपरांत वन संसाधन के संरक्षण, प्रबंधन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
- वन अधिकार प्राप्त हितग्राहियों को आजीविका के लिये मत्स्य एवं जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह के उपयोग के लिये वन अधिकार दिये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। शासकीय योजनाओं के अभिसरण से व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र धारकों को दावा पश्चात् सहायता यथा भूमि समतलीकरण, मेड़-बंधान, खाद-बीज, सिंचाई उपकरण संबंधी सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथ ही इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं किसान सम्मान निधि योजना से भी लाभान्वित किया जा रहा है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला: छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को अंतर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को भोपाल में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करते हुए अंतर्राज्यीय वर्ग में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ को अंतर्राज्यीय वर्ग में स्टॉल को डिस्प्ले एवं विक्रय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।
- गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20 से 26 दिसंबर तक हुआ।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक एस.एस. बजाज ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में राज्य लघु वनोपज द्वारा 140 से अधिक उत्पादों के प्रदर्शन सह-विक्रय के लिये स्टॉल लगाया गया था।
- उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में छत्तीसगढ़ राज्य को बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज की खरीदी के लिये कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने रुचि दिखाई है। 8 व्यापारी संस्थानों ने 200 टन कोदो, कुटकी, रागी, हर्रा, नागरमोथा, बहेड़ा, काचरिया चरोटा बीज, गिलोय और अन्य लघु वनोपज खरीदी चर्चा की और अपनी सहमति भी दी है।
- अंतर्राष्ट्रीय वन मेला में लघु वनोपज आधारित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ और मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के मध्य 6 करोड़ रुपए का व्यावसायिक अनुबंध हुआ।
- छत्तीसगढ़ वनोपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक एस.एस. बजाज और विंध हर्बल्स की ओर से एमपीएमएफपी के सीईओ डॉ. दिलीप कुमार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- इसके अलावा 28 करोड़ 50 लाख रुपए का एमएफपीपीएआरसी और विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापारिक अनुबंध भी किये गए। इस प्रकार कुल 50 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ।
- लघु वनोपज आधारित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में बस्तर फूड छत्तीसगढ़ से महुआ एक्सपोर्ट के लिये एमओयू हुआ। इससे आने वाले समय में जड़ी-बूटियों के क्षेत्र में शामिल प्राथमिक संग्राहक और उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि में मददगार साबित होंगे।
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलन मध्य प्रदेश के सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ह्वी.आर. खरे के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इसमें प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से 140 सहभागी ने प्रत्यक्ष रूप से और 300 प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद किया गया।
- छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के विशेष प्रबंध संचालक एस.एस. बजाज ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्था मैसूर के साथ मिलकर महुआ से गुड़ बनाने पर अनुसंधान कर रहा है।

प्रदेश के सभी ज़िलों में होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण

चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर, 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने के मद्देनज़र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश के सभी ज़िलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा।

प्रमुख बिंदु

- फोर्टिफाइड चावल उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2023 से वितरित किया जाएगा। अंत्योदय, एकल निराश्रित नि:शक्तजन श्रेणी के राशनकार्डधारियों को वर्तमान में दिये जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा।
- गौरतलब है कि सार्वभौम पीडीएस के तहत खाद्यान्न सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा एनीमिया एवं अन्य पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने हेतु नवंबर 2020 से कोंडागांव ज़िले में फोर्टिफाइड चावल वितरण प्रारंभ किया गया है।

नोट :

- वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी ज़िलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी ज़िले (कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाडा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा) तथा 2 हाईबर्डन ज़िले (कबीरधाम एवं रायगढ़) में फोर्टिफाइड चावल का भी वितरण किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि फोर्टिफाइड चावल पोषक एवं स्वास्थ्यवर्धक है। यह आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 से युक्त होता है। इसमें मौजूद आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी-12 जैसे पोषक तत्त्व बड़ों एवं बच्चों में खून की कमी नहीं होने देते हैं तथा खून निर्माण एवं तंत्रिका तंत्र के सही ढंग से कार्य में सहायक होते हैं।
- फोर्टिफाइड चावल के फायदे के संबंध में ज़िले के राशनकार्डधारियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, मितानिन एवं उचित मूल्य दुकानों में बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल को पकाने के तरीके एवं उपयोग के संबंध में समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर, 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लेने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक में राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
  - इसके तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल, 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर, 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा।
  - कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिये शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का विकल्प नोटराईज्ड शपथ-पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
  - शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर 1 नवंबर, 2004 से 31 मार्च, 2022 तक एनपीएस खाते में शासन द्वारा जमा किये गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा।
  - 1 अप्रैल, 2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय सेवक अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
- कैबिनेट की बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिये विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में कुल 780 करोड़ रुपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च किये जाएंगे।
- वाणिज्यिक वृक्षारोपण से पर्यावरण सुधार और किसानों की आय में वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
- प्रदेश में मिलेट्स मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई और राज्य में मिलेट उत्पादन एवं उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कृषि, वन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग, संस्कृति, वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह एवं जेल, वाणिज्यिक कर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- अंतर्विभागीय और अंतर्निकाय से संबंधित केंद्र राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्लस्टर स्तर पर क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु 5 नवीन ज़िलों में ज़िलास्तरीय एग्लोमरेशन एवं ज़िलास्तरीय समिति गठन का निर्णय लिया गया।

नोट :

- एंबुलेंस श्रेणी के वाहनों से जीवनकाल कर उद्ग्रहण हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- वाहनों से अस्थायी पंजीयन कर में वृद्धि किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 एवं नियम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- राज्य के सभी ज़िलों में राज्य योजना के राशनकार्डधारियों (एपीएल को छोड़कर) को फोर्टिफाईड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इसमें 42 करोड़ रुपए की राशि व्यय होगी।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जारी राशनकार्डों में माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 88 दंतेवाड़ा के माननीय विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना की न्यायिक जाँच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर, 2022 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक नई योजना 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'में भाग लेने हेतु इच्छुक कृषक अथवा संस्था अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आगामी वर्ष में रोपण हेतु आवश्यक पौधों की जानकारी सहमति-पत्र के साथ दे सकते हैं।
- गौरतलब है कि इस योजना में कृषकों की निजी भूमि में प्रतिवर्ष 36 हज़ार एकड़ के मान से पाँच वर्षों में एक लाख 80 हज़ार एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों (क्लोनल नीलगिरि, टिशू कल्चर बांस, टिशू कल्चर सागौन, मिलिया डूबिया एवं अन्य आर्थिक लाभकारी प्रजाति) का रोपण किया जाएगा।
- समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध-शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएँ, निजी ट्रस्ट, गैर-शासकीय संस्थाएँ, पंचायतें तथा भूमि अनुबंध धारक, जो अपनी भूमि में रोपण करना चाहते हैं, इस योजना के हितग्राही होंगे।
- 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर (अधिकतम 5000 पौधे) पौधों का रोपण हेतु 100 प्रतिशत तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना में सहयोगी संस्था अथवा निजी कंपनियों की सहभागिता का प्रस्ताव है। उनके द्वारा वित्तीय सहभागिता के साथ शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर हितग्राहियों के वृक्षों की वापस खरीद का प्रस्ताव भी दिया गया है। सहयोगी संस्था अथवा निजी कंपनियों की सहभागिता से कृषकों को उनके उत्पाद के लिये सुनिश्चित बाज़ार उपलब्ध होगा तथा शासन पर वित्तीय भार भी कम होगा। टिशू कल्चर सागौन, टिशू कल्चर बांस एवं मिलिया डूबिया वृक्षों के परिपक्व होने के पश्चात् निर्धारित समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा क्रय किया जाएगा।
- राज्य में इस योजना के अंतर्गत कुल पाँच वर्षों में एक लाख 80 हज़ार एकड़ में रोपित 15 करोड़ पौधे परिपक्व होने के पश्चात् हितग्राहियों को लगभग 5000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होने की संभावना है।
- 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना'के क्रियान्वयन से प्रति वर्ष लगभग 30 हज़ार किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से हितग्राहियों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 15 से 50 हज़ार रुपये तक आय की प्राप्ति होगी।
- योजना के क्रियान्वयन से वाणिज्यिक वृक्षारोपण के रकबे में वृद्धि से काष्ठ आधारित उद्योगों, जैसे- पेपर मिल, प्लाईवुड, फर्नीचर, विनियर इत्यादि के लिये कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नए उद्योगों की स्थापना से स्थानीय निवासियों के रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होगी तथा विभिन्न करों के माध्यम से शासन को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

नोट :